अरावली वन-क्षेत्र विस्तार और सघनता में कमी होना

4144. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरावली वन-क्षेत्र की सघनता और विस्तार में लगातार कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1952 में अरावली वन-क्षेत्र के विस्तार और सघनता की स्थिति की तुलना में 1998 के दौरान इनकी स्थिति क्या है; और

(ग) अरावली वन-क्षेत्र के विस्तार और सघनता में सुधार लाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बित के प्रयोग से वन आवरण मूल्यांकन का कार्य 1987 में शुरू किया गया। अरावली वन क्षेत्र की सघनता तथा विस्तार का मूल्यांकन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा अलग से नहीं किया गया। अरावली की पहाड़ियां, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा दिल्ली राज्यों में फैली हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, 1989—1997 के मूल्यांकन के मध्य इन राज्यों से वनों की सघनता तथा विस्तार दोनों में ही वृद्धि हुई है। तुलनात्मक वन आवरण मूल्यांकन निम्न प्रकार है:

(वर्ग कि०मी०में)

राज्य	1989 मूल्यांकन	1997 मूल्यांकन
हरियाणा	513	604
गुजरात	11,921	12,578
राजस्थान	12,884	13,353
दिल्ली	22	26

(ग) अरावली वनों के विस्तार तथा उनकी सघनता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं:—

(i) राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ii) वनों के विकास के लिए, दो विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं जो हरियाणा तथा राजस्थान के अरावली क्षेत्र के भाग में क्रियान्वयनधीन हैं, निम्नलिखित हैं:—

(क) **हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों में आम भूमियों का पुन:स्थापन:**

यूरोपियन आर्थिक आयोग की सहायता से, इस परियोजना को हरियाणा के चार दक्षिणी जिलों अर्थात् भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव तथा फरीदाबाद में 1990 से क्रियान्वित किया जा रहे हैं। परियोजना का कुल परिव्यय 48 करोड़ रुपए हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा तथा अर्द्ध-शुष्क अरावली पहाड़ियों में हरित आवरण की पुन:स्थापना करना और स्थानीय लोगों की रहन-सहन की दशाओं में सुधार करना है।

(ख) **राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के लिए वानिकीकरण परियोजना**

इस परियोजना को, समुद्र-पार आर्थिक सहयोग निधि, जापान के वित्त-पोषण से, राजस्थान सरकार द्वारा 176.69 करोड़ रुपए की कुल लागत से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, मरुस्थलीकरण को रोकना तथा पुन: वनीकरण के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्थिति को बहाल करना तथा स्थानी य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईंधन लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। परियोजना को राजस्थान के अरावली क्षेत्र के 10 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(iii) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) तथा 3(2)(v) तथा पर्यावरणीय अवक्रमण पैदा करने वाली कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 5(3)(घ) के तहत, हरियाणा के गुड़गांव तथा राजस्थान के अलवर जिले के पूर्व अनुमति के सिवाय, 7 मई, 1992 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

Extent of Forest cover in different States

4145. SHRI K. KALAVENKATA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the extent of forest cover in some of the States is decreasing;

(b) if so, the percentage of forest cover to land area in different States;

(c) the action plan drawn up, if any, to increase the forest cover in different States and for securing enhanced financial allocations for the purpose; and

(d) the fresh centrally sponsored afforestation schemes being undertaken in the State of Andhra Pradesh and the financial allocation made therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) Yes, Sir.

(b) The percentage of forest cover to land area in different States is given in the Statement (*See* below).

(c) The action plan to increase the forest cover in different States and for securing enhanced financial allocations is as under:—

(i) The Ministry has requested the concerned State/UT Governments to take serious note of the depletion of forest cover and to make an in-depth analysis of the factors contributing to the depletion of forest cover, to evolve effective stragety and action programme for arresting the trend so as to increase the forest cover in the coming years.

(ii) Afforestation programmes are undertaken by the State Governments from their own resources and with financial assistance under Centrally Sponsored Schemes and under externally aided projects. A total of 7.86 million ha. of afforestation has been done in the Eighth Plan.

(iii) A Working Group was constituted for recommending frame work of activities in forestry sector for Ninth Five Year Plan taking into account the progress made in implementation of Eighth Plan programmes. The Working Group has proposed an outlay of 21,102 crores for forestry sector in the Ninth Plan including afforestation of around 15 million hectares.

(iv) The Planning Commission has also issued guidelines to all the State Government for restoration of the earmarking of at least 10% funds each under Employment Assurance Schemes and Jawahar Rozgar Yojana for afforestation activities.

(d) The Centrally Sponsored Afforestation Schemes being undertaken in Andhra Pradesh and the financial allocation made is as follows:—

(Rs. in lakhs)

S.No.	Name of the Scheme	Yearly Allocation
1.	Area oriented fuelwood and fodder project scheme	160.00
2.	Integrated Afforestation and Eco-development project scheme	200.00
3.	Non-timber forest produce scheme	46.39
4.	Grants-in-aid scheme	37.43

Statement

Percentage of forest cover to land area as per 1997 Assessment

(in sq. km.)

State/UT	Geographic Area	Forest Cover Per cent
Andhra Pradesh	2,75,068	15.7
Arunachal Pradesh	83,743	81.9
Assam	78,438	30.4
Bihar	1,73,877	15.3
Delhi	1,483	1.7
Goa	3,702	33.8
Gujarat	1,96,024	6.4
Haryana	44,212	1.4
Himachal Pradesh	55,673	22.5
Jammu & Kashmir	2,22,235	9.2
Karnataka	1,91,791	16.9
Kerala	38,863	26.6
Madhya Pradesh	4,43,446	29.6
Maharashtra	3,07,690	15.0
Manipur	22,327	78.0
Meghalaya	22,429	69.8
Mizoram	21,081	89.1
Nagaland	10,579	85.8
Orissa	1,55,707	30.1
Punjab	50,362	2.8
Rajasthan	3,42,239	3.9
Sikkim	7,096	44.1
Tamil Nadu	1,30,058	13.1
Tripura	10,486	52.9
Uttar Pradesh	2,94,411	11.5
West Bengal	88,752	9.4
A&N Islands	8,249	92.3
Chandigarh	114	6.1
Dadra & Nagar Havelli	491	41.5
Daman & Diu	112	2.7
Lakshdweep	32	Nil
Pondicherry	493	Nil
TOTAL	32,87,263	19.27

Measures for Environmental Protection in the North-Eastern Region

4146. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the measures taken up for environment protection in the North-East region;

(b) the amount of assistance so far released for this scheme on State-wise basis; and

(c) the number of States where the State Pollution Control Boards have been created?